

## प्रदेश में हलाल लखे उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध

### चर्चा में क्यों?

18 नवंबर, 2023 को उत्तर प्रदेश में किसी भी उत्पाद पर हलाल प्रमाणन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। यह पाबंदी खाद्य उत्पाद के साथ ही दवाओं पर भी लागू होगी।

### प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश की खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की अपर मुख्य सचिव अनीता सहि ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सभी खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों को नरितर नगिरानी के नरिदेश दयि गए हैं।
- खाद्य उत्पाद के साथ ही दवाओं के उत्पाद के नरिमाण, भंडारण, वतिरण एवं वकिरय पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। हालॉकविदेश भेजे जाने वाले उत्पाद के लयि छूट रहेगी।
- वदिति हो कविदेश में नरियात होने वाले मांस और उससे नरिमति उत्पादों पर हलाल प्रमाण पत्र जारी होता रहा है। धीरे-धीरे तेल, साबुन, घी सहति सभी उत्पादों पर हलाल प्रमाणन की मुहर लगने लगी। मुख्यमंत्री योगी आदतियनाथ के नरिदेश के बाद इसे रोकने की रणनीति बनाई गई और 18 नवंबर को इस पर प्रदेश में पाबंदी लगा दी गई है।
- प्रदेश में हलाल प्रमाणन वाले किसी भी खाद्य उत्पादों एवं दवाओं को स्वीकार नहीं कयिा जाएगा। यदकि कोई उत्पादन हलाल प्रमाणन वाला पाया गया तो संबंधति नरिमाता के खलिाफ कार्रवाई की जाएगी। नरिमाण के साथ ही भंडारण, वतिरण, वकिरय पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दयिा गया है।
- यदकि राज्य में कार्यरत कोई नरियातक अपने खाद्य उत्पाद अथवा दवा को उन देशों के लयि तैयार करता है, जहाँ हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पाद ही स्वीकार कयिे जाते हैं तो उसे छूट दी जाएगी। वह दूसरे देश के लयि तैयार होने वाले उत्पाद का नरिमाण, भंडारण एवं वतिरण कर सकेगा।
- प्रदेश की नयिमावली में हलाल प्रमाणीकरण का कोई नयिम नहीं है। सरिफ गुणवत्ता, पैकगि, लेबलगि सही होनी चाहयि। नए आदेश के बाद यदकि कोई हलाल प्रमाणीकरण युक्त दवाओं, प्रसाधन सामग्री व खाद्य सामग्री तैयार करता है अथवा भंडारण व वतिरण करता है तो उसके खलिाफ अधनियिम 1940 व तत्संबंधी नयिमावली के अधीन कार्रवाई की जाएगी।
- इसके तहत तीन साल का कारावास, एक लाख रुपए जुर्माना, और नयिम 18 ए के तहत छह साल का कारावास अथवा 25 हज़ार का जुर्माना हो सकता है।